>

Title: Need to withdraw the proposed hike in electricity tariff in Daman & Diu.

श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र दमन और दीप में बिजली के दामों को बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर जीआरसी ने अपनी मुहर लगा रखी है जो सभी सैक्टर, जैसे कि घरेलू खेती, उद्योग सभी पर लागू किया है। मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर अवगत कराना चाहूंगा कि घरेलू क्षेत्र में मात्र दो फीसदी बिजली का उपयोग दमन और दीव में किया जाता है जबकि 98 फीसदी उद्योग क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि दमन और दीव दिसम्बर, 1961 में भारत में शामिल हुआ था और इस वजह से दमन और दीव का विकास बाकी क्षेत्र के मुकाबले में बहुत धीमी गति से हुआ है। यहां के विकास के लिए लगाए जाने वाले उद्योगों को टैक्स होलीडे और कम दाम में बिजली उपलब्ध करायी गई थी। दमन दीव में टैक्स होलीडे खत्म कर दिया गया है। दमन दीव की जनता के लिए उद्योगों में बिजली ही एक लाइफ लाइन बची है। अगर बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे तो इस क्षेत्र में गहरा नुकसान हो सकता है जिससे कई उद्योगों पर ताला लग सकता है। इसके चलते दमन दीव में बेरोजगारी बढ़ सकती है और अर्थ तंत्र बिगड़ सकता है।

महोदय, मत्स्य उद्योग एग्रीकल्चर का एक भाग होता है। इस क्षेत्र में दी जाने वाली बिजली उद्योग को दिए जाने वाले दाम में दी जाती है, मैं समझता हूं कि यह गलत है। दीव में आइस बनाने वाली फैक्ट्री मत्सय उद्योग का एक हिस्सा है इसलिए बिजली इस उद्योग को खेती क्षेत्र को दिए जाने वाले दाम पर मिलनी चाहिए क्योंकि आइस मछली पकड़ने वाली बोट में यूज होता है। मैं आज इस जगह से खड़ा होकर बताना चाहता हूं कि दमन और दीव करीब 3500 करोड़ रुपया रेवेन्यु भारत सरकार को देता है जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है क्योंकि यह रेवेन्यु भारत के दूसरे सबसे छोटे क्षेत्र से आता है। मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर आफ पावर से अनुरोध करता हूं कि बिजली के दाम में जीआरसी जो बढ़ोत्तरी करना चाहती है उसे तत्कालिक स्थगित किया जाए, इसे लागू न किया जाए और दमन दीव को और मजबूत बनाने में मदद की जाए।